

भाजपा राज करने के लिए नहीं, बल्कि देश बदलने के लिये राजनीति करती है-भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरु किया

जयपुर, 3 सितंबर (का.सं.) भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी और डॉ प्रेमचंद बेरवा को पार्टी का सदस्य बनाकर प्रदेश में सदस्यता अभियान का आगाज किया। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने का



मु.मंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ ही प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज हो गया।

भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत की है। अब भाजपा, प्रदेश के साथ-साथ जिलों में सघन अभियान चलाएगी। भाजपा के कार्यकर्ता इस अभियान को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लेकर जाएंगे और मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जनता के साथ चर्चा करेंगे। भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉ अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ यह अभियान शुरु हुआ अब 4 सितंबर को प्रदेश के प्रत्येक जिले में भाजपा के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रेसवार्ता के माध्यम से अभियान को लॉन्च करेंगे।

चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा प्रदेश में सवा करोड़ सदस्यों को पार्टी परिवार का सदस्य बनाएगी। इसलिए राजस्थान के 51 हजार 700 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं को 200-200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। भाजपा सदस्यता अभियान के तहत 88 00 00 2024 नंबर पर मिस्ट्र कॉल का य नमो ऐप, वेबसाइट और व्हाट्सएप कोड स्कैन करके कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। यह अभियान दो चरणों में चलेगा। इसका पहला चरण 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।

राजस्थान के 51,700 बूथों पर 200-200 सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेंगे, भाजपा कार्यकर्ता-डॉ. अरूण चतुर्वेदी।

आ न किया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को पार्टी की रीति-नीति और पंच निष्ठाओं से अवगत कराते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनाएं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को पर-घर जाकर हर परिवार से संपर्क करना है और सदस्य बनाना है। अगर कोई अभियान से जुड़ना नहीं चाहता है तो भी उसे पार्टी की रीति- नीति जरूर बताएं। भाजपा कार्यकर्ता सवा करोड़ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। हम सब जन प्रतिनिधिगण अपने क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाने में सक्रिय

कीनिया में प्रमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एयरपोर्ट को खरीदने के प्रयास में हैं। लेकिन इसके विरोध में स्थायी वकर्स ने हड़ताल कर दी है। उनकी मुख्य चिंता नौकरी को लेकर है।

इस वर्ष के आरंभ में अडानी ने कीनिया एयरपोर्ट्स अधिारिटी को जोमो कीनियाटा एयरपोर्ट चलाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें नया टर्मिनल, टैक्सी वे सिस्टम आदि के लिए 750 मिलियन डॉलर के निवेश का प्रस्ताव था। इसके अलावा अन्य सुधार कार्यों के लिए 92 मिलियन डॉलर अतिरिक्त देने का प्रस्ताव है। यह सारा कार्य 2035 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

अडानी नए एयरपोर्ट बनाने के लिए भी 620 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। कम्पनी शहर के समीपवर्ती क्षेत्र में होटल, बिजनेस सेंटर आदि भी खोलना चाहती है।

अडानी 30 साल के लिए एयरपोर्ट का संचालन करना चाहते हैं। उसके बाद यह कीनिया की सरकार को लौटा दिया जाएगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीच बैंक से वेतन के रूप में 16.80 करोड़ रूपए लिए थे।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज से नोटिस के जरिए स्पष्टीकरण जारी किया और कहा, माधवी पुरी बुच को बैंक छोड़ने के बाद जो राशि दी गई थी वह वेतन या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन नहीं है बल्कि रिटायरमेंट बैनिफिट्स हैं।

कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आई.सी.आई.सी.आई. के स्पष्टीकरण की विसंगतियों पर सवाल उठाया।

खेड़ा ने कहा, तथाकथित रिटायरमेंट बैनिफिट्स में राशि व समय के हिसाब से इतनी विसंगति क्यों है, इतने वर्षों में भुगतान में काफी भिन्नता रही है। उन्होंने आगे कहा कि आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा माधवी बुच को 2016-17 और 2020-21 के बीच जो तथाकथित रिटायरमेंट बैनिफिट्स मिले थे वे 277 लाख अर्थात् 2.77

करोड़ रूपए थे, जबकि 2016 से 2021 के बीच उन्हें आई.सी.आई. सी.आई. से 1.3 करोड़ रूपए बतौर वेतन मिले थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को वेतन से ज्यादा रिटायरमेंट बैनिफिट्स मिलें हों।

कांग्रेस नेता ने आई.सी.आई.सी.आई. के स्पष्टीकरण पर जवाबी प्रहार करते हुए कहा कि क्या कोई भी कर्मचारी, जिसमें सेवानिवृत्त भी शामिल हैं, को पद से हटने के दस साल बाद ई.ए.एस.ओ.पी. के लेने का अधिकार रखता है।

आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा सार्वजनिक रूप से बताई गई ई.ए.एस.ओ.पी. नीति कर्मचारी को पद छोड़ने के मात्र तीन माह के भीतर ही बैनिफिट्स लेने का विकल्प देती है।

इसके आधार पर खेड़ा ने कहा, वह संशोधित नीति कहें हैं, जिसके तहत माधवी बुच नौकरी छोड़ने के 8 साल बाद भी ई.ए.एस.ओ.पी. हासिल करने में सफल हुईं।

स्पैम कॉलिंग के लिए 50 संस्थायें ब्लैक लिस्ट हुईं

नयी दिल्ली 03 सितंबर (वार्ता) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देशों पर सेवा प्रदाताओं ने स्पैमिंग के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुये 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया है तथा 2.75 लाख से अधिक एसआईपी डीआईडी/मोबाइल नंबर/दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काट दिया है। ट्राई ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इन कदमों से स्पैम कॉल में कमी आने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की आशा है। ट्राई ने सभी हितधारकों से निर्देशों का पालन करने तथा स्वच्छ और अधिक दक्ष दूरसंचार

टैलिकॉम रैगुलेटरी अधिारिटी ऑफ इंडिया ने इन संस्थाओं के अलावा 2.75 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों एवं मोबाइल इत्यादि के कनेक्शन काट दिये हैं।

इकोसिस्टम में योगदान देने का आग्रह किया है। वर्ष 2024 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में अपंजीकृत टेलीमाकेटर्स (यूटीएम) के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज होने के मद्देनजर ट्राई ने पाया है कि स्पैम कॉल में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ट्राई ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 13 अगस्त 2024 को सभी सेवा प्रदाताओं को कड़े निर्देश जारी किए। इसने सेवा प्रदाताओं को एसआईपी, पीआरआई या अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों या टेलीमाकेटर्स की ओर से होने वाले प्रमोशनल वॉयस कॉल को तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

आर.पी.एस.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बजट सत्र में घोषणा की गई है कि प्रदेश में चार लाख सरकारी नौकरियां दी जायेंगी, जिनमें से एक लाख सरकारी नौकरियां मार्च, 2025 तक दी जायेंगी। ऐसे में इन सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं और इसकी चयन प्रणाली में पूरी पारदर्शिता होने के साथ ही, परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं और उनके माता-पिता में परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रति विश्वसनीयता कायम रखना सरकार का दायित्व है।

राहुल गांधी हरियाणा में आप से गठबंधन के इच्छुक हैं

पर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा गठबंधन के पक्ष में नहीं लगते

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 सितम्बर। अगले माह होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होने की सम्भावना गति पकड़ रही है। समझा जाता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी की राज्य इकाई से आग्रह किया है कि चुनावों में भाजपा की हार की सम्भावनाओं को अधिकतम स्तर तक पहुँचाने की खातिर इस गठबंधन को एक मौका दे।

यद्यपि हरियाणा के चुनावों में अब मात्र एक महीना रह गया है तथा राजनैतिक दलों की तैयारियाँ पूरे जोर पर हैं, फिर भी ये दोनों दल राज्य विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन को जारी रखने के प्रबल आकांक्षी प्रतीत हो रहे हैं। ज्ञातव्य है कि दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव इन दोनों दलों ने मिलकर लड़े थे।

आप नेता संजय सिंह ने आज इन मीडिया रिपोर्टों का स्वागत किया। राहुल गांधी अगले माह होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए दोनों पार्टियों में सम्भावित गठबंधन के बारे में कांग्रेस के नेताओं की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं।

सिंह ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से विचार-विमर्श करने के बाद ही लिया जायेगा। ज्ञातव्य है कि आप-प्रमुख केजरीवाल दिल्ली एक्साइज नीति, जो अब रह हो चुकी है, में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में जेल में बन्द हैं।

समाचार एजेंसी ए.एन.आई. ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उद्धृत करते हुए कहा, "हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी सन्दीप पाठक तथा (राज्य इकाई के अध्यक्ष) सुशील गुप्ता इस मामले में अंतिम निर्णय लेकर, उसकी जानकारी अरविन्द केजरीवाल को देंगे। उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।"

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा ने

हुड्डा ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है, पर, हरियाणा में गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। हुड्डा गठबंधन की अधिकतम 3-4 सीटें आप को देने को ही राजी हो सकते हैं।

अगर, गठबंधन हुआ भी तो सीटों के बंटवारे पर काफी जबरदस्त सौदेबाजी होने की संभावना है।

आप को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके ज्यादा लाभ नहीं हुआ था, हालांकि, कांग्रेस को काफी फायदा हुआ था। कांग्रेस 10 संसदीय सीटों में से पाँच पर विजयी हुई थी, जबकि, इससे पहले भाजपा ने 10-0 के स्कोर से सभी सीटें जीती थीं।

कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का था। हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। यहाँ लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है।" इस साल के शुरू में हुए लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने हरियाणा में पाँच सीटें जीती थीं तथा 2019 की तुलना में काफी सुधार हुआ था। 2019 में, भाजपा ने राज्य की 10 लोकसभा सीटें जीती थीं। आप ने लोकसभा में हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीती थी।

इससे पूर्व, केजरीवाल ने कहा था कि आप अकेली ही राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझा जाता है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कल आप के साथ गठबंधन करने के मामले में पार्टी नेताओं की राय जानने के लिए पार्टी की चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई थी। सूत्रों ने कहा कि हुड्डा 90 सीटों वाले सदन के चुनाव में आप उम्मीदवारों को अन्य सीटें ही देने के लिए तैयार हैं। समझा जाता है कि कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है तथा कल उम्मीदवारों की एक सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन के बारे में चर्चा को लेकर अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा है।

पता चला है कि राहुल गांधी ने आप के साथ गठबंधन की व्यवहार्यता पर पार्टी नेताओं से रिपोर्ट माँगी है। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के प्रान्तीय नेताओं ने

इस विचार को खारिज कर दिया है, लेकिन हाईकमान ने उनसे जमीनी स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा कि हाईकमान अगली साल होने वाले दिल्ली के चुनावों पर भी विचार कर रही है कि राजधानी के चुनावों के लिए पार्टी आप के साथ गठबंधन कर सकती है या नहीं। हरियाणा में इंडिया ब्लॉक की बड़ी जीत सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक और धक्का होगा। कांग्रेस नेतृत्व की नजर विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने तथा संसद के अन्दर और बाहर भाजपा पर दबाव डालने पर रहेगी। हरियाणा की जीत के लिए, वोटों को बँटने से रोकना बहुत जरूरी एवं महत्वपूर्ण है। इसलिए, कांग्रेस गठबंधन करने पर ध्यान दे रही है, बशर्ते कि राज्य-नेतृत्व इससे सहमत हो जाए। कांग्रेस और आप ने हरियाणा की 10 सीटों तथा चन्डीगढ़ की संसदीय सीट के लिये गठबंधन किया था। जहाँ कांग्रेस ने हरियाणा में पाँच सीटों के साथ, चन्डीगढ़ सीट भी जीती थी, वहीं आज को गठबंधन से कोई खास लाभ नहीं हुआ था। चुनाव-परिणाम के कुछ समय बाद ही, हरियाणा के आप नेताओं के एक वर्ग ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र दोषारोपण कांग्रेस पर किया था। इस पृष्ठ भूमि के चलते, ऐसी सम्भावना है कि इन विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आप के बीच किसी भी प्रकार की वार्ता में दोनों पक्ष अधिक से अधिक सीटें चाहेंगे।

क्या गणित है राहुल का आप से चुनावी गठबंधन में?

यह प्रश्न इसलिये उठ रहा है, क्योंकि, आम धारणा है कि वातावरण वैसे ही कांग्रेस के पक्ष में है, इस बार हरियाणा में

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। इस प्रश्न ने बड़ी उत्सुकता एवं जिज्ञासा पैदा कर दी है कि ऐसे समय पर, जब मतदान-विशेषज्ञ हरियाणा के आसन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत की साफ-साफ भविष्यवाणी कर रहे हैं तो फिर राहुल ने आप के साथ सीट शेयरिंग डील प्रस्तावित क्यों की है? क्या ऐसा इसलिए है कि वे भाजपा-विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहते हैं? या फिर उनका यह मानना है कि भाजपा की ही तरह, आप भी शहरी-क्षेत्र आधारित पार्टी है तथा इसलिए अरविन्द केजरीवाल को साथ लेने से भगवा पार्टी को बड़ी चुनौती दी जा सकेगी? या इसका कारण यह है कि वे विपक्ष के नेता की नई भूमिका में यह दिखाना चाहते हैं कि उनका

क्या इस प्रतीकात्मक एडजस्टमेंट से राहुल मानते हैं कि झारखंड व महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में फायदा मिलेगा।

वैसे यह भी सच है कि आप को भाजपा की भाँति एक शहरी पार्टी माना जाता है। अतः अगर आप और कांग्रेस में हरियाणा चुनाव में गठबंधन हुआ तो आप भाजपा के वोट काटेगी और अंततोगत्वा कांग्रेस को लाभ पहुँचायेगी।

साथ ही आप-कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो, राहुल यह मानते हैं कि एन्टी-भाजपा वोटों का विभाजन, बिखराव नहीं होगा चुनाव में।

एक लाभ यह भी है कि हरियाणा में दरियादिली दिखाकर राहुल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और मजबूती से सौदेबाजी कर सकते हैं, आप से।

दिल कितना बड़ा है? या फिर हरियाणा में कोई समझौता प्रस्तावित करके, वे

प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा था। पंजाब की परिधि से लगी कुछ सीटों, तथा भौगोलिक रूप से दिल्ली के पास की कुछ सीटों, जैसे फरीदाबाद या गुरुग्राम के अलावा, आप की स्थिति हरियाणा में मजबूत नहीं है।

पार्टी ने इस साल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था तथा आप उम्मीदवार भाजपा के नवीन जिन्दल से लगभग 29,000 वोटों से हारे थे।

लेकिन उनके अच्छे प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिन्दल के खिलाफ, आप प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। दरअसल, जिन्दल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे।

कांग्रेस और आप के बीच के चुनाव पूर्व गठबंधन से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं मिलना है लेकिन समझौते का इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, आप प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। दरअसल, जिन्दल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। कांग्रेस और आप के बीच के चुनाव पूर्व गठबंधन से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं मिलना है लेकिन समझौते का इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, आप प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। दरअसल, जिन्दल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। कांग्रेस और आप के बीच के चुनाव पूर्व गठबंधन से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं मिलना है लेकिन समझौते का इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, आप प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। दरअसल, जिन्दल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे।

अन्तर्राष्ट्रीय निवेश लाने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को आयोजित हो रही "राइजिंग राजस्थान" समित प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि समित के माध्यम से निवेशकों को न केवल प्रदेश की औद्योगिक विकास क्षमता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, अपितु वे विकसितराजस्थान की यात्रा में मजबूत सझेदार बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समित में निवेश के लिए आप लाने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पूरी कर ली जाएं। रोड-शो एवं अन्य निवेश संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में

सामंजस्य स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समित का उद्देश्य देश-विदेशी कंपनियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना है।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुभाष पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अठावाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अलोक गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक रीको शिवप्रसाद नकाते सहित उच्च अधिकारियों को मौजूद था।

ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अवॉर्ड वापसी मूवमेंट शुरु हुआ

बंगला सिनेमा के प्रमुख अभिनेता सुदीप्त चक्रवर्ती, चंदन सेन और बिप्लव बनर्जी ने अवॉर्ड वापस करते हुये कहा है कि सरकार ने जनता की भावनाओं व न्याय की मांग को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है

कोलकाता, 3 सितम्बर। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि बंगाली मनोरंजन जगत के प्रमुख कलाकार अपने-अपने अवॉर्ड लौटाने लगे हैं। इस मामले को लेकर बंगाल में सियासी

माहौल गरमा गया है। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है। आम हो या खास कई लोग डॉक्टरों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब बंगाली फिल्म और थियेटर के कलाकार गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि बंगाली मनोरंजन जगत के प्रमुख कलाकार अपने-अपने अवॉर्ड लौटाने लगे हैं। इस मामले को लेकर बंगाल में सियासी

सुदीप्त चक्रवर्ती, चंदन सेन और बिप्लव बनर्जी जैसे मझे हुए कलाकारों

ने राज्य सरकार से मिले अवॉर्ड को वापस करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सरकार ने जनता की भावनाओं और न्याय की मांग को नजरअंदाज किया है, जिससे वे बेहद आहत हैं।

ममता सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर टीएमसी विधायक केचन मलिक ने टिप्पणी करते हुए कहा

कि जो कलाकार राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार से मिले सम्मान को वापस कर देना चाहिए। केचन मलिक के इस बयान के बाद बंगाली कलाकारों का गुस्सा फूट रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तक विजेता अभिनेत्री सुदीप्तो चक्रवर्ती ने स्पेशल फिल्म अवॉर्ड लौटाने का फैसला किया है।

ममता की पुलिस ने माना, जाँच ठीक तरीके से नहीं हुई

-अंजन राँय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, विनीत गोयल ने आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमण्डल के सामने स्वीकार किया है कि सरकारी अस्पताल, आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज में मृत डॉक्टर का शव मिलने के बाद पुलिस फ्राइम सीन को सुरक्षित करने और मामले की जांच करने में असफल रही है।

आंदोलनकारी डॉक्टरों ने आज सेंट्रल कोलकाता के लाल बाजार क्षेत्र में स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया। छात्रों को फिजर्ज लेन तथा बैन्टिक स्ट्रीट क्षेत्र में रोका गया तथा पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया।

आंदोलनरत छात्र आज सेंट्रल कोलकाता में सड़कों पर बैठे रहे और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की।

पुलिस ने अंततः 22 जूनियर डॉक्टरों को एक प्रतिनिधिमण्डल के रूप में पुलिस कमिश्नर से मिलने और उनके समक्ष अपनी माँग रखने

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और स्वीकार किया कि पीड़िता का शव मिलने के बाद घटना स्थल की सुरक्षा करने व मामले की जाँच करने में पुलिस पूरी तरह से विफल हो गई है।

जूनियर डॉक्टरों मंगलवार को भी दिनभर सड़क पर बैठे रहे, उनकी माँग थी, कमिश्नर इस्तीफा दें।

कमिश्नर से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने धरना तो खत्म कर दिया, पर, कहा कि न्याय मिलने तक विरोध प्रदर्शन व आंदोलन जारी रहेगा।

इसी बीच ममता बनर्जी एक बिल लाई हैं, जिसमें रेप के अपराधी को त्वरित दंड का प्रावधान है। पर, जनता पर उनके इस कदम का असर नहीं हो रहा, क्योंकि रेप के मामलों में ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है और रेप पीड़िताओं के प्रति उनकी सोच बेहद निंदनीय रही है।

की इजाजत दे दी। तथापि, डॉक्टरों ने अपना आंदोलन समाप्त करने से इन्कार कर दिया तथा न्याय की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस या सी.बी.आई. ने अभी तक संदिग्ध लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं तथा ये तत्व स्वतंत्र घूम रहे हैं। ये प्रश्न उठ रहे हैं कि सरकार इन संदिग्धों तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए ढाल का काम क्यों कर रही है।

ज्यादातर लोग इस समय विद्रोह के मूड में हैं तथा संदिग्धों की गिरफ्तारी की माँग कर रहे हैं। लोगों ने पास एरिया से लगे हुए पूर्वी महानगरों में असाधारण रूप से लम्बी मानव श्रृंखला आयोजित की।

इस बीच, राज्य सरकार रेप के अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए एक विधेयक लाई है। यह विधेयक ममता बनर्जी ने पेश किया।

लेकिन सरकार के इस कदम का लोगों पर कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि रेप-केसों की है-डलिंग में मुख्यमंत्री का ट्रैक-रिकॉर्ड बहुत अन्यापूर्ण ही रहा है।

आज डॉक्टरों ने अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे राष्ट्रगान से की। जूनियर डॉक्टरों के साथ राष्ट्रगान में शहर के कुछ अत्यधिक ख्यातिप्राप्त डॉक्टर भी शामिल थी जब विरोध-